

प्रेषक,

डॉ० आनन्द श्रीवास्तव,

अपर सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

पिथौरागढ़।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 06 मई, 2022

विषय:-जनपद पिथौरागढ़, तहसील धारचूला के ग्राम गर्व्यांग में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के हैलीपैड के उपयोगार्थ 0.500 है० गौचर भूमि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के नाम सःशुल्क आवंटन तथा उक्त भूमि के एवज में 0.500 है० बंजर काबिल आबाद भूमि को गौचर में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-934/सात-20/2021-22, दिनांक 16 मार्च, 2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल को हैलीपैड के उपयोगार्थ तहसील धारचूला पट्टी गुंजी, ग्राम गर्व्यांग के गैर जमींदारी विनाश खतौनी श्रेणी-9(3)ग गौचर के खाता संख्या-50 के खेत नम्बर 17 मध्ये 0.500 है० भूमि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के नाम आवंटन करने की स्वीकृति प्रदान करने तथा उक्त भूमि के एवज में ग्राम गर्व्यांग के गैर जमींदारी विनाश खतौनी, श्रेणी-9(3)ड़ बंजर काबिल आबाद के खाता संख्या-51 के खेत नम्बर 33 मध्ये रकबा 0.250 है०, 35 मध्ये रकबा 0.250 है कुल 02 खेतों की 0.500 है० राज्य भूमि गौचर में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद की सामरिक महत्ता एवं अन्तर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल को हैलीपैड के उपयोगार्थ तहसील धारचूला पट्टी गुंजी, ग्राम गर्व्यांग के गैर जमींदारी विनाश खतौनी श्रेणी-9(3)ग गौचर के खाता संख्या-50 के खेत नम्बर-17 मध्ये 0.500 है० भूमि जिसका मूल्य रू० 5,25,600.00 (पांच लाख पच्चीस हजार छः सौ रुपये मात्र) होता है, को शासनादेश संख्या-496/XVII(II)/2020-08(63)/2016 दिनांक 28 जुलाई, 2020 में दी गयी व्यवस्थानुसार गृह मंत्रालय, भारत सरकार के नाम सःशुल्क आवंटन करने तथा उक्त भूमि के एवज में ग्राम गर्व्यांग के गैर जमींदारी विनाश खतौनी, श्रेणी-9(3)ड़ बंजर काबिल आबाद के खाता संख्या-51 के खेत नम्बर 33 मध्ये रकबा 0.250 है०, 35 मध्ये रकबा 0.250 है कुल 02 खेतों की 0.500 है० राज्य भूमि शासनादेश संख्या-1332/XVII(II)/2014-18(58)/2013, दिनांक 07 जुलाई, 2014 में दी गयी व्यवस्थानुसार गौचर में परिवर्तित करने की अनुमति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

...2

- 1- प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी। जिलाधिकारी पहले इसे सुनिश्चित करेंगे। तदनुसार वन विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही पट्टा निष्पादन की कार्यवाही करेंगे।
- 2- चूंकि जिलाधिकारी द्वारा संबंधित शासनादेश दि०-१५.१९८४ के अधीन निर्धारित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्राविधानों का अनुपालन अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
- 3- इस संबंध में सिविल अपील संख्या-११३२/२०११ (एस०एल०पी०)/(सी) संख्या-३१०९ /२०११ श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 4- प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत दी गयी है।
- 5- प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार पट्टेदार को नहीं होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से ०३ वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- 6- प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-१५०/१/८५(२४)-रा-६ दिनांक-०९ अक्टूबर, १९८७ में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट १८९५ के अधीन पट्टा प्रथमतः ३० वर्षों के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार ३०-३० वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढ़ाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के १-१/२ गुना से कम नहीं होगा।
- 7- प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को नहीं रह जायेगी तो भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।
- 8- यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भागों से मुक्त निहित हो जायेगी।
- 9- भू-उपयोगिता व पट्टे में इंगित शर्तों के कम में शासन/जिलाधिकारी/अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकता है।
- १०- विभाग द्वारा शासनादेशानुसार नजराने एवं मालगुजारी की जमा करायी गई धनराशि की प्राप्ति रसीद/चालान की प्रति तत्काल शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

11— आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों बिन्दु संख्या-01 से 10 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

3— कृपया इस सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश एवं इस शासनादेश की शर्तों की अनुपालन स्थिति से भी अनिवार्य रूप से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by Anand
Srivastava

Date: 06-05-2022 16:06:08

(डॉ० आनन्द श्रीवास्तव)

अपर सचिव,

संख्या-589/XVIII(II)/2022 तददिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2— आयुक्त, कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
- 3— सेनानी, 07वीं वाहिनी आई0टी0बी0पी0 मिर्ठी, तहसील डीडिहाट, पिथौरागढ़।
- 4— निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
- 5— गार्ड फाईल।